

उदारीकरण की विनाशकारी नीतियों के विरुद्ध संघर्ष करो

चेन्नई में 22 से 25 अप्रैल तक हुई सी आई टी यू जनरल काउंसिल की बैठक ने देश की अर्थव्यवस्था और आम आदमी के जीवन में अंधकार भर रही आर्थिक उदारीकरण की विनाशकारी नीतियों के खिलाफ शांति-पीड़ित जनता के अन्य तबकों के साथ मिलकर मजदूर वर्ग के संयुक्त आंदोलन का निर्माण करने के लिए अपने प्रयास और तेज करने का निर्णय लिया है। चुनाव पूर्व के घटनाविकास और चुनावोत्तर परिदृश्य की व्यापक समीक्षा करने की प्रक्रिया में जनरल काउंसिल ने सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ व्यापक अभियान छेड़ने का भी संकल्प लिया। इन ताकतों के खतरनाक खेल और खास तौर से भाजपा के नेतृत्व को गठबंधन को केंद्र में सरकार बन जाने के बाद के उनके खतरनाक खेल और खास तौर से भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन की केंद्र में सरकार बन जाने के बाद के उनके खतरनाक खेल को बेनकाब करने के लिए यह अभियान छेड़ा जायेगा।

सी आई टी यू की तमिलनाडु राज्य कमेटी ने इसके लिए व्यापक इंतजाम किए थे कि जनरल काउंसिल प्रभावी तथा अर्थपूर्ण ढंग से अपनी चार दिवसीय विचार-विमर्श की कार्यवाही पूरी करे। बैठक के मंच का नामकरण दिवंगत कामरेड लीलावती के नाम पर किया गया था। तमिलनाडु ट्रेड यूनियन नेता की अप्रैल 1997 में मालिकान के गुंडों ने हत्या कर दी थी।

शोषित-पीड़ित जनता के महानेता और उसके संघर्षों के सिद्धांतकार कामरेड ई एम एस नंबूदिरिषाद और सीटू उपाध्यक्ष कामरेड थिमल सिन्हा, जिनकी जनरल काउंसिल की बैठक के कुछ हफ्ते पहले ही त्रिपुरा में उग्रवादियों ने हत्या कर दी थी, के निधन पर शोक प्रस्ताव पेश करने के साथ सी आई टी यू जनरल काउंसिल की बैठक का उद्घाटन सत्र शुरू हुआ। उद्घाटन सत्र में ही "सांप्रदायिकता के खिलाफ" भी एक प्रस्ताव स्वीकार किया गया जिसमें सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ संघर्ष में जनता के दूसरे तबकों के साथ मिलकर मजदूर वर्ग की व्यापक एकता का निर्माण करने के लिए उसके संकल्प को सुबद्ध किया गया था।

दुनिया के स्तर पर

गहराता आर्थिक संकट

अपने अध्येक्षीय भाषण में ई बालानंदन ने आर्थिक तथा राजनीतिक दोनों ही क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटनाविकास पर रैशनी डालते हुए साम्राज्यवादी ताकतों और खासतौर से अमरीकी प्रशासन के, तीसरी

दुनिया के विकासशील देशों पर आर्थिक और राजनीतिक दोनों ही तरह के अपने प्रभुत्व का विस्तार करने के, जी-तोट्ट प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने क्यूबा और इराक की नाकेबंदी में अमरीकी हेकड़ी और फिलिस्तीन तथा अन्य जगहों के घटनाविकास की जानकारी भी दी। दक्षिणपूर्व एशियाई अर्थव्यवस्थाओं, जिनमें एक जमाने में एशियाई शेर कहा गया था, के गहराते संकट का जिक्र करते हुए बालानंदन ने इस दावे के खोखलेपन को उजागर किया कि वैश्वीकरण तथा उदारीकरण की तथाकथित नीति से संबंधित राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का विकास होगा तथा ये समृद्ध होंगी। इसके विपरीत वैश्वीकरण की ऐसी नीति को लागू करने के पीछे इरादा बहुराष्ट्रीय निगमों के साम्राज्य को विकासशील देशों में फैलाना तथा उसे सुदृढ़ करना ही होता है और यह नीति बेरोजगारी और गरीबी को और बिगाड़ने तथा आम जनता के बीच आर्थिक असमानता की खाई को और चौड़ा करने का ही काम करती है और यह असर विकासशील देशों में ही नहीं होता बल्कि विकसित औद्योगिक देशों में भी होता है। और खासतौर से पूर्ववर्ती सोवियत संघ तथा पूर्वी यूरोप में समाजवादी व्यवस्था के पतन के बाद विश्व पूंजीवाद मानव जाति के प्रति और ज्यादा क्रूर हो गया है और साथ ही साथ उसने जनतंत्र तथा संप्रभुता के लिए गंभीर खतरा पैदा कर दिया है और इस तरह अपने आपको "मानव भक्षी पूंजीवाद" और "गिद्ध पूंजीवाद" के रूप में प्रकट कर रहा है। बालानंदन का कहना था कि खुद पूंजीवादी शिविर, के प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने उसे ये संज्ञाएं दी हैं।

राष्ट्रीय स्थिति का जिक्र करते हुए बालानंदन ने मजदूर वर्ग और जनता की एकता के समक्ष उपस्थित खतरे और खासतौर से भाजपा के नेतृत्ववाले गठबंधन के केंद्र में सत्तासीन होने के बाद पैदा हुए खतरे के चिंताजनक आयामों की ओर संकेत किया और इस गठबंधन और इस खतरे के असली चेहरे के प्रति लोगों में और ज्यादा जागृति पैदा करने की जरूरत पर जोर दिया। उनका कहना था कि "हमें निचले तथा ऊपर के दोनों ही स्तरों से मजदूर वर्ग को एकजुट करने के लिए कोई भी क्रीशिश उठा नहीं रखनी चाहिए ताकि मजदूर वर्ग को एक वर्ग के रूप में इस सांप्रदायिक हमले और साथ ही साथ विश्व बैंक द्वारा निर्देशित आर्थिक नीतियों का मुकाबला करने के लिए आगे लाया जा सके."

नये घटना विकास के दूरगामी असर होंगे

सी आई टी यू महासचिव एम के पंधे द्वारा जनरल काउंसिल के

समक्ष रखी गयी महासचिव की रिपोर्ट में अक्टूबर 1997 में शिमला में आयोजित सीटू वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद के देश में सामने आये घटनाविकास को रखा गया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि इस घटनाविकास के "भारत के राजनीतिक तथा आर्थिक परिदृश्य पर दीर्घाविध प्रभाव पड़ेगे।" रिपोर्ट में यह बात जोर देकर कही गयी थी कि भाजपा के नेतृत्व में सांप्रदायिक ताकतों द्वारा केंद्र में सरकार बना लेने के देश के मजदूरवर्ग के लिए गंभीर परिणाम होंगे जिनका ट्रेड यूनियन आंदोलन प्रभावी ढंग से सामना करना होगा।

अपनी रिपोर्ट में पंथे ने साफ शब्दों में इस बात को रेखांकित किया कि भाजपा द्वारा सत्ता हथिया लिये जाने की पृष्ठभूमि, "किसी को आर एस एस की उस खतरनाक भूमिका को कम करके नहीं आंकना चाहिए, जो पदों के पीछे से वह अंदा करने जा रहे हैं। प्रशासनिक व्यवस्था, सेना और अन्य दूसरे संगठनों...जिनमें मीडिया भी शामिल है, में उसकी घुसपैठ का, कुछ समय बाद सरकार गिर जाने की स्थिति में, भयानक असर होगा।"

तथाकथित उदारीकरण की नीतियों को और व्यापक बनाने तथा उन्हें और तेज करने की भाजपा सरकार की घोषणा का जिक्र करते हुए पंथे का कहना था कि उसके सत्ता ग्रहण करने के एक महीने के भीतर ही सरकार ने आयात-निर्यात नीति संबंधी ज़िप कदमों की घोषणा की है वे इस प्रक्रिया के और तेज होने की खतरनाक प्रवृत्ति को ही दिखाते हैं, जो देश की आत्मनिर्भरता और मजदूर वर्ग तथा आम जनता के हितों के लिए नुकसानदेह है। पंथे का कहना था कि तथाकथित उदारीकरण की नीति के लागू होने के सात साल बाद भी अर्थव्यवस्था में जबरदस्त मंदी साफतौर पर यह स्थापित कर देती है कि उदारीकरण की आड़ में एफ और एफ बिश बैंक की नीति, जिसके प्रति भाजपा सरकार पहले ही अपन एफ और एफ की घोषणा कर चुकी है, का भारत की अर्थव्यवस्था या भारत की जनता के हितों से कुछ भी लेना देना नहीं है, सिवाय बहुराष्ट्रीय कंपनियों को मुनाफा पहुंचाने के।

राष्ट्रीय एजेंडा

बेनकाव

भाजपा गठजोड़ के "राष्ट्रीय एजेंडा" को बेनकाव करते हुए, जो कि "हवाई वादों की पोतली के अलावा कुछ नहीं है" पंथे ने कहा कि उन्होंने स्वदेशी को मजाल बनाकर रख दिया गया है जबकि आयातों के और उदारीकरण और अन्य रियायतें देने के जरिये वे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के स्वागत में ताल कालीन बिछा रहे हैं और "इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि अगर आइ एम एफ और बिश बैंक ने भाजपा के स्वदेशी के नारे को सही समझा है और राष्ट्रीय एजेंडा का स्वागत किया है" और "बहुराष्ट्रीय निगमों के साथ करीबी संबंध रखने वाली एक चौकड़ी पहले ही पैदा हो चुकी है और बड़े भारतीय पूंजीपति वर्ग का एक मजबूत तबका अपनी वफादारी बदलकर भाजपा के प्रति वफादार हो गया है।"

आर्थिक नीति के मुद्दों के अलावा संविधान संशोधन के प्रति भाजपा

सरकार की नीति, भारतीय समाज में मौजूदा सांस्कृतिक तथा धार्मिक भिन्नता आदि के प्रति उसका रुख और इसके साथ ही साथ शिव सेना, बजरंग दल आदि विभिन्न सांप्रदायिक संगठनों द्वारा दूसरे धर्मों तथा दूसरी संस्कृतियों के प्रति सत्ताधारी पार्टी के प्रत्यक्ष समर्थन के जरिये प्रदर्शित की जा रही असहनशीलता आदि सभी ऐसी बातें हैं जिनका भारतीय समाज के बहुलतावाद, जनतांत्रिक ढांचे और देश की एकता तथा अखंडता के लिए खतरनाक परिणाम होंगे,

खिलासतौर से चुनावोत्तर स्थिति ने जो चुनौतियां पेश की हैं और एक तरफ उदारीकरण की नीतियों तथा दूसरी ओर सांप्रदायिक ताकतों के हमलों का मुकाबला करने का मजदूर वर्ग के समक्ष जो भारी काम है उसकी पृष्ठभूमि में महासचिव की रिपोर्ट में सीटू की सांगठनिक स्थिति का भी जायजा लिया गया था। उसकी देश भर में फैली विभिन्न इकाइयों और फेडरेशनों के कामकाज और उनमें गरुहता के स्तर पर विचार किया गया था।

संगठित की पहलकदमियों को

दुगना करो

रिपोर्ट में स्पष्ट शब्दों में इस बात की पहचान की गयी थी कि सी आइ टी यू को अपने संगठन को सुदृढ़ करने और सामने उपस्थित संकट के प्रतिव्यपक जागरूकता और जो काम सामने है उसकी गहरी समझ बनाने के लिए अपनी पहलकदमियों को दुगना करना होगा। रिपोर्ट में कहा गया था कि मजदूर वर्ग के बीच सांप्रदायिकता के खतरनाक परिणामों और सत्ता में बैठी सांप्रदायिक पार्टी तथा उसकी विभिन्न शाखाओं की गतिविधियों के प्रति जागरूकता पैदा करते हुए शक्तिशाली विचारधारात्मक अभियान चलना आंदोलन के सामने उपस्थित प्रमुख कामों में से एक है, महासचिव की रिपोर्ट में आइ एम एफ-बिश बैंक द्वारा निर्देशित आर्थिक नीति के खिलाफ चौरफा संघर्ष को और तेज करने की फौरी जरूरत को भी रेखांकित किया गया था क्योंकि इसी सांप्रदायिक गठबंधन ने इस नीति को पूरे जोर-शोर से जारी रखने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही साथ ट्रेड यूनियन आंदोलन के बीच भी इस मुद्दे पर व्यापक एकता का निर्माण करना होगा।

महासचिव की रिपोर्ट पर दो दिन तक चली बहस में चालीस प्रतिनिधियों ने भाग लिया, बहस में भाग लेते हुए उन्होंने अपने अनुभव रखे और साथ ही साथ महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए।

बहस का जवाब देते हुए महासचिव एम के पंथे ने आर्थिक नीति के खिलाफ संघर्ष में आम मजदूर तथा जनता के दूसरे तबकों को एकजुट करने के लिए बिल्कुल निचले स्तर पर सक्रिय पहलकदमी करने की फौरी जरूरत को रेखांकित किया। उनका कहना था कि राष्ट्रीय स्तर पर दूसरी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और जनसंगठनों के साथ विचार-विमर्श की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है और यह दोनों स्तरों पर चल रही है: ट्रेड यूनियन की आयोजन समिति के स्तर पर भी और जन संगठनों के राष्ट्रीय मंच के स्तर पर भी ताकि देशव्यापी आंदोलन का एक कार्यक्रम तैयार किया जा

सके। पर हमारी पहलकदमी व्यापक लाभबंदी में मददगार होंगी। पंचे ने वार्गीय और जन एकता की रक्षा के लिए सांप्रदायिकता के खिलाफ सघन अभियान जारी रखने की जरूरत पर भी जोर दिया।

सी आइ टी यू उपाध्यक्ष आर उमानाथ ने बहस में हस्तक्षेप करते हुए सांप्रदायिकता के खतरे के खिलाफ मजदूरों को जागृत करने की फौरी काम की तरफ ध्यान आकृष्ट किया।

अपने समापन भाषण में बालानंदन ने भी तमाम संबद्ध यूनियनों का आह्वान किया कि शोषण के खिलाफ और जनता की एकता की रक्षा के लिए संपर्क में मजदूरवर्ग को व्यापक एकता का जल्द से जल्द निर्माण करने के काम को हाथ में लें।

असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की स्थिति

जनरल कार्डसिल ने "असंगठित क्षेत्र के मजदूरों" की स्थिति पर विचार-विमर्श के लिए एक अलग सत्र का आयोजन किया था। विचार-विमर्श के लिए इस सत्र में एक अलग पर्चा प्रस्तुत किया गया था। पी के गांगुली ने यह पर्चा पेश किया जिसमें इस विराट क्षेत्र, जिसमें कि शहरी गैरकृषि श्रमशक्ति का 73 फीसद हिस्सा लगा हुआ है, में सीटू का विस्तार करने के ठोस सांगठिक कार्य को सूत्रबद्ध किया गया था। अतीत के अनुभवों और कमियों की गहरी समीक्षा के बाद इस काम को सूत्रबद्ध किया गया है।

इस पर्व पर हुई बहस में 20 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यह निर्णय लिया गया कि सभी राज्यों में असंगठित क्षेत्र में काम के क्षेत्र की प्राथमिकता और राज्य स्तर पर उनकी पहचान के लिए ठोस पहलकदमियों की जाय। सभी राज्य कमेटियों को असंगठित क्षेत्र में काम की निगरानी के एकमात्र काम के लिए छः महीने के भीतर एक सब-कमेटी का गठन करना चाहिए और राज्य स्तर की समन्वय समितियों को सक्रिय करना चाहिए, यह भी निर्णय लिया गया कि संगठित क्षेत्र के भीतर काम कर रहे असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को संगठित करने के लिए और मुख्यतः टेका मजदूरों, जिनकी संख्या निर्दिष्ट न बढ़ती ही जा रही है, को संगठित करने के लिए पहलकदमी करनी चाहिए।

ई एम आइ योजना का सुधारो

सीटू सचिव काली घोष द्वारा पेश किए गए एक आलेख के आधार पर ई एस आइ योजना के कामकाज पर एक अलग से बहस आयोजित की गयी। इस पर्व में इस तथ्य को सामने लाया गया था कि ई एस आइ योजना के लिए मजदूरों के अंशदान की एक अवधि के बाद केवल सरकार के पास ई एस आइ के फंड में बढ़ोतरी ही होती जाती है और मजदूरों को इसका कोई लाभ नहीं मिलता और उनकी स्थिति में सुधार होने की बजाय, वह बिगड़ती ही चली जाती है।

इस विषय पर विचार-विमर्श में 12 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और ई एस आइ के काम काज में सुधार समेत उसके लाभों को बेहतर बनाने के लिए देशव्यापी संपर्क छेड़ने का सुझाव दिया। केंद्रीय अधिकारियों ने हाल ही में ई एस आइ को संबंधित राज्य सरकारों को सौंप देने का जो

सुझाव दिया, उसका सभी संबंधित लोगों ने कड़ा विरोध किया है।

इस योजना के काम में सुधार की ठोस मांगों को लेकर और उसकी प्रमात्रा को मांगों को लेकर और उसकी प्रमात्रा को व्यापक बनाने और इसके लाभों का दायरा बढ़ाने के लिए देशव्यापी अभियान छेड़ने का निर्णय लिया गया। इस सिलसिले में आगामी 18 जून को ई एस आइ योजना पर मांग दिवस मनाने का निर्णय भी लिया गया। देश भर में ई एस आइ कार्यालयों पर जनतामबंदी-प्रदर्शनों आदि के जरिये यह दिवस मनाया जायेगा।

जनरल कार्डसिल ने अनेक प्रस्ताव स्वीकार किए इनमें प्रमुख हैं: हरियाणा के कपड़ा मजदूरों पर पुलिस की गोलीबारी, पेंशन योजना के खिलाफ संघर्ष, मूल्य सूचकांक की नयी शृंखला शुरू करने की सरकार की कोशिश के खिलाफ, सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के आंदोलन पर, गुप्त मतदान के जरिये ट्रेड यूनियनों को मान्यता देने पर, आंध्र प्रदेश के बिजली मजदूरों के संघर्ष के समर्थन में, तमिलनाडु के मजदूरों के संघर्ष के समर्थन में, तमिलनाडु के मजदूरों के संघर्ष के समर्थन में, महिला मजदूरों के दैनिक शोषण के खिलाफ और आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक के किसानों की दुर्दशा पर तथा आत्महत्या के वाक्यों और इस सिलसिले में किसानों की स्थिति में सुधार के लिए फौरन कदम उठाने की मांग करते हुए।

जनरल कार्डसिल ने केंद्र सरकार द्वारा तमिलनाडु सरकार के खिलाफ धारा 356 के इस्तेमाल करने की कोशिशों की निंदा करते हुए भी सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया। प. बंगाल, त्रिपुरा और केरल की वामपंथी तथा वामपंथी-जनतांत्रिक सरकारों को बधाई देते हुए एक और प्रस्ताव भी पारित किया गया।

इसके अलावा जनरल कार्डसिल ने अपनी तमाम इकाइयों का आह्वान किया कि मजदूरों और कार्यकर्ताओं की चेतना का स्तर उठाने के लिए उनके बीच जबरदस्त विचारधारात्मक अभियान चलायें और उन्हें शिक्षित करें ताकि वे सांप्रदायिकता और आर्थिक उदारीकरण तथा वैश्वीकरण के दोहरे खतरे के खिलाफ जोरदार संघर्ष के लिए तैयार हो सकें। जनरल कार्डसिल ने कम्युनिस्ट घोषणापत्र की 150वीं सालगिरह मनाने का संकल्प लिया और अपनी तमाम इकाइयों का आह्वान किया कि इस महान अवसर को सघन विचारधारात्मक अभियान और शिक्षण गतिविधियों के जरिये मनायें।

विशाल रैली

सीटू जनरल कार्डसिल की चार दिवसीय बैठक के समापन के मौके पर 25 अप्रैल को चेन्नई में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया जिसमें हजारों: हजार मजदूरों ने भाग लिया। तमिलनाडु में सीटू के वरिष्ठ नेता सुंदरराजन ने रैली की अध्यक्षता की। रैली को संबोधित करने वालों में सीटू अध्यक्ष ई बाला नंदन, महासचिव उम के पंधे, सीटू की तमिलनाडु राज्य इकाई के महासचिव टी के रंगराजन, सीटू उपाध्यक्ष आर उमानाथ और सचिव ए के पद्मनाभन मुख्य थे।